भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 673 का उत्तर

झारखण्ड में रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण

673. श्री पशुपति नाथ सिंहः
श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका सर्वेक्षण कर लिया गया है और स्वीकृति प्रदान कर दी गई है लेकिन उन पर कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) उक्त परियोजनाओं की परियोजना-वार मौजूदा स्थिति क्या है; और
(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि सर्वेक्षित परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जा सके?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। ।

****

झारखण्ड में रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण के संबंध में 20.11.2019 को लोक सभा में श्री पशुपति नाथ सिंह और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के अतारांकित प्रश्न संख्या 673 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): इस समय, रेलवे द्वारा झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 30 रेल परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें 1463 कि.मी. लंबी और 25535 करोड़ रुपए की समग्र लागत वाली 14 नई लाइन परियोजनाएं और 1145 कि.मी. लंबी 14485 करोड़ रुपए की समग्र लागत वाली 16 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं नियोजन/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना दर परियोजना और स्थल दर स्थल भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंततः कार्य समापन स्थिति पर गणना की जाती है।

परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने ठेकों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन अवधारणा अपनाई है, जिससे परियोजनाओं के निष्पादन में और तेजी आएगी।

क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

समग्र राष्ट्र के हित में और निर्माण कार्यों के निर्बाध निष्पादन के लिए रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तंर, क्षेत्रीय स्तर एवं बोर्ड स्तर) पर अत्यधिक निगरानी रखी जाती है तथा राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों का समाधान किया जा सके।

******